स्थिरता व आत्मनिर्भरता वाला बजट; रक्षा, इन्फ्रा, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर

स्पेशल इकोनॉमिक जोन से घरेलू व्यापार में तेजी आएगी

बजट से युवा और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर

बनेंगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर नियमों में ढील देना बड़ा कदम है जिससे घरेलू व्यापार बढ़ेगा। खनिज क्षेत्र के लिए नए कॉरिडोर और टैक्स छूट से आम लोगों को फायदा होगा। **-अनिल अग्रवाल**, चेयरमैन, वेदांता

भविष्य की नींव रखेगा देश को 'धुरंधर' बनाएगा

बजट भविष्य की नींव रखने वाला है। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी

और डेटा सेंटर व परमाणु ऊर्जा पर जोर भारत को 'धुरंधर' बनाएगा। इससे युवाओं के कौशल विकास, समावेशी विकास और टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कोशिश है। **-हर्ष गोयनका**, चेयरमैन, आरपीजी

वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने में मदद मिलेगी

बजट में बायोफार्मा को सात रणनीतिक क्षेत्रों में शामिल करते

हुए 'बायोफार्मा शक्ति' योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 5 साल में 10 हजार करोड़ खर्च होंगे। इससे दवा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश वैश्विक बायोफार्मा हब बनेगा। **-किरण मजूमदार शॉ**, बायोकॉन

10 हजार करोड़ रु. का फंड एसएमई के लिए फायदेमंद

10 हजार करोड़ रु. का 'एसएमई ग्रोथ फंड' और सूक्ष्म उद्योगों के

लिए 2,000 करोड़ की सुविधा छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा सहारा है। सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने से उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। **-सी.एस. शेट्टी**, चेयरमैन, एसबीआई

चार नए रेयर अर्थ कॉरिडोर से ईवी कार सस्ती होंगी

लिथियम-आयन सेल बनाने वाली मशीनों पर कस्टम ड्यूटी छूट और

चार नए रेयर अर्थ कॉरिडोर से ईवी गाड़ियां सस्ती होंगी। छोटे डीलरों के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड व सीएनजी पर ड्यूटी राहत भरे कदम हैं। दुर्घटना मुआवजे पर टैक्स छूट से राहत मिली है। **-सी.एस. विग्नेश्वर**, अध्यक्ष, फाडा

किफायती आवास के लिए घोषणा न होने से निराशा

रियल एस्टेट के लिए निराशा रही। किफायती आवास के लिए बड़ी

घोषणा नहीं हुई, इन घरों की बिक्री 2019 के 38% से गिरकर 2025 में मात्र 18% रह गई है। इस क्षेत्र के खरीदारों और डेवलपर्स के लिए ब्याज राहत जैसे सीधे हस्तक्षेप की सख्त जरूरत थी। **-अनुज पुरी**, चेयरमैन, एनरॉक

डेटा सेंटर्स पर टैक्स छूट से भारत वैश्विक हब बनेगा

12.2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कैपेक्स निजी निवेश और विकास

को रफ्तार देगा। डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स हॉलिडे से भारत वैश्विक हब बनेगा। शेयर ऑप्शन पर एसटीटी से बाजार में उतार-चढ़ाव संभव है। **-नीलेश शाह**, एमडी, कोटक महिंद्रा एएमसी

मोटर एक्सीडेंट क्लेम के ब्याज पर टैक्स से छूट सही

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के ब्याज पर टीडीएस और टैक्स

से छूट देना बेहतर कदम है। जिससे पीड़ितों को मुआवजा मिलना आसान होगा। शेयर बायबैक को कैपिटल गेन की तरह टैक्स करना छोटे निवेशकों के लिए फायदेमंद है। **-अश्वनी धनवत**, सीआईओ, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस